पशुधन संरक्षण

वर्ष : 1 ● अंक 7 ● अक्टूबर-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान

पशुपालकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता

अभियान के दौरान अब तक 3 लाख 13 हजार से अधिक पशुओं का उपचार

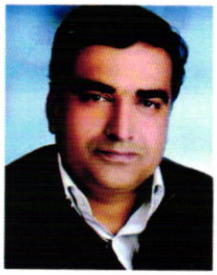

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में चलाये जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अब तक अयोजित 1785 शिविरों में 3 लाख 13 हजार से अधिक पशुओं का उपचार किया गया। यह जानकारी देते हुए कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि पशुपालकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 को सफलतापूर्वक संचालित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से जुड़े विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता एवं सेवा भाव के साथ लोगों के कामो को पूरा करें, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आयी तो सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले हर फरियादी की समस्या को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनें और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं।

शासन सचिव पशुपालन विभाग डॉ. आरुषी मलिक ने बताया कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित कर उन्हें राहत देना इस प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 का मुख्य लक्ष्य है। अभियान के तहत पशुपालन गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा. प्रकाश भाटी को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया गया है, इसके अतिरिक्त समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों पर भी जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से पशुपालकों को विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओ की जानकारी देने के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों के बचाव हेतु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, रोगी एवं अस्थाई रूप से बांझ पशुओं का उपचार तथा पशु परजीवी रोगों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा दी जा रही है। डॉ. मलिक ने बताया कि डेयरी, भेड़-बकरी एवं मुर्गीपालन के लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवर्ति लागत जिसमें श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने, बिजली व पानी, पशु चिकित्सा एवं पशु बीमा हेतु अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए पशुपालकों के आवेदन पत्र भी तैयार किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर से 17 दिसम्बर, 2021 तक चलने वाले 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान 22 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य सम्पादित किए जाएंगे।